



VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M N 31 AUG 2022 **No. 3**
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1839)

Name of Candidate	SUSHMA SAGAR		
Medium Eng./Hindi	HINDI	Registration Number	1370539
Center	MAA	Date	31/8/22

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

- Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
- There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI** इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
- All questions are compulsory.**
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
- Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar
Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. An independent umbrella body that brings the various central investigative agencies under one roof holds the key to shoring up their credibility. Discuss. (150 words) 10

एक स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय जो विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक छत के नीचे लाता हो, उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाने की कुंजी है। विवेचना कीजिए।

भारत में विभिन्न प्रकार की जांच एजेंसियाँ कार्यरत हैं जैसे - CBI, ED (उर्वरक निदेशालय) SPID (गंभीर अपराध जांच संगठन) आदि।

एक स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय की आवश्यकता

→ कार्य में अतिव्यापन होना

विभिन्न एजेंसियों द्वारा एक ही मामले में बिना-बिना साक्ष्य जुटाए जाते हैं, बिना बयान दिए जाते हैं जिससे जाटिलता बढ़ जाती है।

→ संसाधनों की कमी

स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय से संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होगा व मानव व वित्तीय संसाधनों की कमी दूर होगी।

→ कुशलता व दक्षता का आना

बेहतर समन्वय होगा।

जनता की जाँच पकैली में विश्वसनीयता बढ़ना —

↳ राजनीतिक दलसे प को कम दिया जा सकेगा। इसी के कारण SC ने 2013 में CBI को केंद्र में वेद चिंजरी कहा था।

↳ पारदर्शिता में बढ़ावा

↳ जबाबदेहिता सुनिश्चित होगी।

↳ जटिलताएँ कम होगी इससे

आम नागरिक की भागीदारी बढ़ेगी
(मामलों को समझने में सहायता)

लेकिन निम्न बातों का भी

ध्यान रखा जाना चाहिए

→ स्वतंत्र व राजनीतिक दलरूप अध्ययन होना।

→ पत्राचार शक्तियाँ दी जाए

→ पत्राचार मानव व विनियम समाधान दिए जाए।

→ स्वायत्ता प्रदान की जाए

→ राज्यों के साथ सहयोग को बढ़ावा

ए- 9 राज्यों ने CBI से आम सहमति वापस ले ली। अतः अम्बेला नियम से

जाँच पकैली को मजबूत बनाया जा सकेगा।

2. Discuss the significance of the Doctrines of Pith and Substance and Colourable Legislation with respect to Centre-state relations in India.

(150 words) 10

भारत में केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में तत्व एवं सार के सिद्धांत और छद्म (आभासी) विधायन के सिद्धांत के महत्व की विवेचना कीजिए।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची व समवर्ती सूची के माध्यम से राज्य व केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया गया है।

लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिससे विषय का सूची के आधार पर निर्धारण नहीं हो पाता। अतः न्यायिक पुनरावलोकन की दृष्टि से तत्व व सार का सिद्धांत व छद्म विधायन का सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

तत्व व सार का सिद्धांत व इसका महत्व

- यह सिद्धांत कानून के तत्व अर्थात् कंटेन्ट व उसके सार के आधार पर विषय का निर्धारण करता है।
यू-आर्दे संघ सूची का सार है तो

इसे राज्य सूची का अतिक्रमण नहीं माना जाएगा।

- विषयों के निश्चयण में लोचशीलता (flexibility) देता है।
- यह न्यायिक पुनरावलोकन में कानून के तार को महत्व देता है।
- विषयों के निश्चयण से राज्य-क्षेत्र के मध्य सहयोगात्मक लक्ष्यवाद को बढ़ावा देता है।

द्विधम विधायन का सिद्धांत व महत्व

इसके अनुसार, कोई चीज जो प्रत्यक्ष रूप से अवैध है वो अप्रत्यक्ष रूप से भी अवैध है।

- यह सरकारों के कानूनों के अतिक्रमण को रोकता है।
- प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र निश्चित करता है।
- कानून की पवित्रता बनाए रखता है।
- कानून के दुरुपयोग के संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदान करता है।

3. Do you agree with the view that there should be simultaneous elections to the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies in India? Discuss with suitable arguments. (150 words) 10

क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ होने चाहिए? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए।

भारत में 1967 तक लोक सभा व राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ होते थे।

एक साथ चुनाव के लाभ -

+ संसाधनों की बचत

↳ बड़ी मात्रा में धन का व्यय हो जाता है।

↳ सरकारी कर्मचारियों व अद्वैतापकों को नियोजित किया जाता है।

+ बाले धन पर रोक व दुरुता में

हद है
- चुनाव के दौरान सामाजिक तनाव-का
कमजोर कर दिया जाता है अतः
ऐसी आर्थिक कम हो जा सकती है।

- मॉडल आचार संहिता लागू
रहने के कारण विकास योजनाएँ
प्रभावित होती हैं जिसका नकारात्मक
प्रभाव कमजोर वर्ग को पड़ता है।

एक साथ चुनाव में चुनौतियाँ -

- राज्यों में सहमति बनाया जाना विशेषकर उनमें जहाँ अभी तक 5 साल पूरे नहीं हुए हैं।
- बार-बार चुनाव से पार्टियों की जवाबदेही बनी रहती है।
- राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं।
- इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया जाना, देश की सुरक्षा को सुगंदा बना सकते हैं।
- संसाधनों का अभाव
- मध्य- में आविश्वात पुस्ताव पारित हो गया तक की परिस्थिति के संदर्भ में चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

जन भागीदारी,
पत्राप्त चर्चा, सही हितधारकों
से सौवाद स्थापित करके व पथर
श्रमता निर्माण के बाद एक देश
एक चुनाव की संकल्पना को
अपनाया जा सकता है।

4. Discuss the need for codification of parliamentary privileges in India, in light of the uncertainty and ambiguity around them. (150 words) 10

भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में अनिश्चितता और अस्पष्टता के आलोक में, उनके संहिताकरण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

भारत में अनु. 105 के तहत
संसदीय विशेषाधिकारों की रचना
की गई है। जिनमें से कुछ
इस प्रकार हैं -

- एक निश्चित अवधि तक दीवानी
मामलों में डिफेंडरों से छूट
- सदन की कार्यवाही के प्रसारण पर
रोक
- सदन में रहें गए व्यक्तियों की
न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया
जाता आदि।

इसका मूल उद्देश्य संसदीय
लोचशील, स्वतंत्र व समावेशी बनाना
था।

विशेषाधिकारों के संहिताकरण की
आवश्यकता

→ संसदीय गारिमा के विरुद्ध
इस विशेषाधिकारों का दुरुपयोग
हो रहा है।

- कथनों के माध्यम से अन्य
संसदों व व्यक्तियों की गारिमा
का उल्लंघन किया जाना।
- संसदीय विपक्ष गमन का बंदना।
- न्यायिक पुनरावलोकन दिया जा
सकेगा।
- नियमों के मध्य स्पष्टता आएगी।
- बेहतर आचरण के लिए
बाध्य किया जा सकेगा।
- जनता का विश्वास बढ़ेगा।
- संसद की उत्पादकता में वृद्धि
होगी जिससे लोकतंत्र मजबूत
होगा।

इस प्रकार विशेषाधिकारों
के संहिताकरण के माध्यम से
जवाबदेहिता को सुनिश्चित
दिया जा सकेगा जिससे
लोकतंत्र मजबूत होगा।

5. While the Civil Services Board can be a step forward in making the Indian bureaucracy more effective, it has its own issues which need to be addressed. Analyse. (150 words) 10

हालांकि, सिविल सेवा बोर्ड भारतीय नौकरशाही को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम हो सकता है, लेकिन इसके अपने मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिए।

सिविल सेवा बोर्ड उच्च स्तर के सिविल सेवा संबंधी नियमों जैसे - पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सिविल सेवा बोर्ड की महत्ता

→ सिविल सेवा में अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है।

→ कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होगी है।

→ सिविल सेवा के कार्यों में वृद्धि व कुशलता आती है।

→ सिविल सेवा की जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी है।

→ जनता का विश्वास बढ़ता है।

सिविल सेवा बोर्ड से संबंधित मुद्दे

→ सभी राज्यों ने ये बोर्ड अभी तक

स्थापित नहीं किए हैं।

- मात्र सलाहकारी शक्तियाँ
- सलाहकों का अभाव
- विज्ञान शक्तियों का अभाव
- वर्ड की सिफारिशों का अनुपालन
न किया जाना।
- इससे प्रशासनिक अधिकारियों
की कार्य सुरक्षा सुरक्षा प्राप्त होने
के कारण कार्यपालिका के प्रति
जवाबदेहिता कम हो सकती है।
- क्रियाओं में पारदर्शिता का अभाव

आगे के रास्ते -

- पर्याप्त सलाहकार उपलब्ध कराना
- अनुशंसाओं के अनुपालन को
निश्चित किया जाना चाहिए।
- इसमें की राजनीतिक हस्तक्षेप को
कम किया जाए।
- हितों का संघर्ष दूर किया जाए क्योंकि
सिविल सेवकों की सिविल सेवकों के
प्रति निर्णय लेते हैं।
- इसकी जवाबदेहिता निश्चित
की जाए।

6. Highlight the potential of India Digital Ecosystem Architecture (IndEA) 2.0 in transforming the ecosystem of service delivery in India. (150 words) 10
भारत में सेवा वितरण के पारितंत्र को रूपांतरित करने में इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर (IndEA) 2.0 की क्षमता पर प्रकाश डालिए।

इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम
आर्किटेक्चर (IndEA) 2.0 देश में
डिजिटलीकरण से संबंधित
अवसरचना, निर्माण, नियमन व
लैरक्षण से संबंधित पारितंत्र है।

IndEA 2.0 की भूमिका व क्षमताएँ

- इसके माध्यम से देश में डिजिटल सेवाओं से संबंधित परस्परता (Uniformity) को बढ़ावा मिलता है।
- देश में डिजिटल सेवाओं के संचरण में अंतरप्रचालन (Inter-operability) बढ़ती है।
- डिजिटल ढाँचा मजबूत होता है इसके लिए पर्याप्त नवाचार व अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है।
- डिजिटल सेवा, AI आदि के माध्यम

में डेटा एकत्रण, विश्लेषण
में सहायता।

→ डेटा के आधार पर नागरिक-केन्द्रित
सेवाओं के संदर्भ में निर्णय-
निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग
करता है।

→ कमजोर वर्गों के समावेशन
पर बल

→ किनटेक, एडूटेक, मेडिटेक,
आदि को बढ़ावा।

→ देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
मानकों के अनुरूप तैयार करना।

जिसे इसके साथ ही
देश में डिजिटल डिविड, डिजिटल
साक्षरता, इंटरनेट की पहुँच,
डिजिटल कौशल निर्माण,
निजता की सुरक्षा, डेटा संरक्षण
आदि पर भी पर्याप्त ध्यान
दिए जाने की आवश्यकता है।

7. What is Civil Registration System? Highlight its importance and discuss the measures taken by the government to bring about improvements in it.

(150 words) 10

नागरिक पंजीकरण प्रणाली क्या है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए और इसमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली में देश के नागरिकों से संबंधित मूलभूत जानकारी जैसे - जन्म, मृत्यु आदि के संदर्भ में रिकॉर्ड रखा जाता है।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली का महत्व

- नागरिकों को देश में कानूनी अधिकार प्राप्त होता है।
- देश की जनसांख्यिकी की जानकारी होना।
- योजनाओं का लक्ष्यीकरण के साथ क्रियान्वयन संभव।
- बेहतर नियंत्रण निमंत्रण।
- देश जनसांख्यिकी लाभोश, लैंगिक अनुपात आदि के शीत से तारगेह विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।

नागरिक पंजीकरण योजना में
सरकार द्वारा किए गए उपाय -

- प्रक्रिया को डिजिटलीकृत करना
- वर्मिक व्यक्तियों को पंजीकृत
प्रशिक्षण देना।
- पुराने रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
करना।
- जन-जागरूकता बढ़ाना करना
- तकनीक का उपयोग

हालांकि निम्न ध्यान

रखा जाना चाहिए -

- डेटा का संरक्षण
- साइबर अपराध, बुलिंग
आदि का खतरा
- कमजोर वर्ग का सुभेद्य होना
- निजता की सुरक्षा

8. The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013, provides an effective mechanism for empowerment of the intended beneficiaries in the society. Critically discuss.

(150 words) 10

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 समाज में इच्छित लाभार्थियों के सशक्तीकरण के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

मैला ढोने की उधा को प्रतिबंधित करने व मानवीय गर्व के दृष्टि से 2013 में मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध व उनका पुनर्वास अधि. 2013 लाया गया था।

2013 के एक्ट की मुख्य बातें एवं विधान

- हाथ से मैला ढोने की उधा को प्रतिबंधित करना।
- सम्भवतः तरीके से लाभार्थियों को पहचान करना।
- उन्ही कोशल निर्माण व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- पुनर्वासित किया जाना।
- अस्वच्छता मुक्त मानकों व उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

इस एक्ट में व्याप्त कमियाँ
व अन्य चुनौतियाँ

- इससे शुद्ध शीपालयों के निर्माण पर प्रतिक्रिया नहीं है।
- सुरक्षा उपकरणों के साथ यह इस उद्योग को जारी रखता है अर्थात् पूर्ण प्रतिक्रिया नहीं लगाया गया है।
- उद्योग का अभाव होने के कारण लाभार्थियों की पहचान नहीं की जा सकी है।
- इसके कारण, पुनर्वास कोशल निर्माण भी नहीं हुए हैं।
- जाति आधारित विविधता को समर्थन देने के पथ पर प्रावधान नहीं है।

अतः आवश्यकता है

कि उद्योग उद्योगों के बाव इस सर्वजनशील वर्ग को पर्याप्त सुरक्षाएं दी जाए ताकि वे अमानवीय स्थितियों में निर्वासित व मृत्यु होने तक मजबूर न हों।

9. Discuss the reforms that must be undertaken to strengthen the World Trade Organisation in order to address the vulnerabilities in the present global trading system. (150 words) 10

वर्तमान वैश्विक व्यापार प्रणाली में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन को सुदृढ़ करने हेतु उस पर किए जाने वाले सुधारों की विवेचना कीजिए।

बढ़ती वैश्विक अंतर्संबंधता के साथ वैश्विक व्यापार प्रणाली की महत्ता भी बढ़ी है।

वर्तमान वैश्विक व्यापार प्रणाली में विद्यमान कमियाँ

- संरक्षणवाद को मिलता बढावा
↳ कोविड महामारी के बाद इस प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है।
- महामारी के दौरान उत्पन्न अनिश्चितताएँ
↳ आपूर्ति श्रृंखला के पूरी तरह टूट जाने ने इसमें विद्यमान कमियों को उजागर कर दिया।
- पश्चिमी प्रतिनिधित्व की कमी
↳ विकसित देशों के पक्ष में आर्थिक सुकाव
- विवाद प्रणाली कमजोर होना
↳ विकसित, अ-विकसित देशों को न्याय नहीं मिल पाता

कमियों को दूर करने हेतु
आवश्यक सुधार

- विवाद निपटान 5011ली को मजबूत किया जाए।
- विकासशील व अविकसित देशों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।
- वस्तुओं के साथ सेवाओं के व्यापार पर भी महत्व दिया जाना।
- डंपिंग व अवमूल्यन जैसी जातिविरोधियों से निपटने के लिए मजबूत तंत्र विकसित करना।
- विकसित देशों से विकासशील देशों में तकनीकी हस्तांतरण किए जाना।
- संरक्षणवादी नीतियों को निपटने हेतु देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना।
- अंतराष्ट्रीय व्यापार में पुनर्मता लाने के लिए विश्व व्यापार 5011ली को पुनर्दृष्टि दिया जाना वर्तमान समय की अनिवार्यता है।

10. State the significance of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Also, discuss the need for a legally binding Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ) agreement.

(150 words) 10

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के महत्व का उल्लेख कीजिए। साथ ही, कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय अधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (BBNJ) समझौते की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

UNCLOS का संवैधानिक समुद्री क्षेत्र व इसके संसाधनों से संबंधित बेहतर विनियमन से है।

UNCLOS का महत्व

- सतत संवर्धनीय रूप से समुद्री संसाधनों का दोहन सुनिश्चित करता है।
- देशों के मध्य सहयोग बढ़ाना।
- समुद्री संसाधनों पर किसी एक देश का समूह के एकाधिकार को रोकना।
- समुद्री संबंधित कानूनों के अनुपालन को बनाए रखना।
- देशों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करना।
- समुद्री कानून के संवैधानिक देशों को विशेषज्ञता प्रदान करना।

राष्ट्रीय आधिकार से परे क्षेत्रों
की समुद्री जैव विविधता
BBNJ समझौते की आवश्यकता

- लगातार बढ़ता अनियमित
दौहन
- जलवायु परिवर्तन की समस्या
 - ↳ कोरल ब्लैचिंग
 - ↳ समुद्री जल स्तर का बढ़ना
 - ↳ वायुमान में बढ़ोत्तरी
- जलीय जैवविविधता पर
नकारात्मक प्रभाव
- लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था - खनन
की चट्टानों
- अर्थव्यवस्था में बढ़ावा
- चीन जैसे देशों द्वारा आधिकार
को बढ़ावा देना।
- इस प्रकार BBNJ से
बेहतर समुद्री जैव विविधता की
पुरस्सा सुनिश्चित की जा सकती
है।

11. Critically assess the role played by the National Human Rights Commission as a watchdog of human rights violations in India. (250 words) 15

भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रहरी के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
का गठन मानव अधिकार
संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत
किया गया था जिसे 2006 में
संशोधित किया गया।

मानवाधिकारों के प्रहरी के रूप में
NHRC की महत्ता

मानवाधिकार के उल्लंघन
से संबंधित मामलों की
जांच करना इसके दो माध्यम

• याचिका द्वारा प्राप्त मामले
• स्वतः संज्ञान (suo moto)
से प्राप्त मुद्दे

मानवाधिकार से संबंधित कानूनों

से संबोधित अपनी विशेषज्ञता
उठान कर कानूनों का स्वरूप
समावेशी बनाया जाना।

+ विभिन्न मंचों व कार्यक्रमों
के माध्यम से मानवाधिकारों
के प्रति जनता को जागरूक
किया जाना।

+ मानवाधिकारों के उल्लंघनों के
संबंध में सरकारों को जवाबदेही
सुनिश्चित करना।

NMRC द्वारा निर्धारित गई भूमिका
का मूल्यांकन

+ इसकी अनुशंसा सलाहकारी प्रवृत्ति
की होती है अतः अधिकारिता:
इसका अनुपालन करने की सरकार पर
बाध्यता नहीं होती।

+ स्वतः संज्ञान आधारित मामलों में
कमी आना, आयोग की सक्रियता

में कमी दर्शाता है

→ अपरिचित मानव व अन्य तकनीकी
संसाधन

→ लोअर केलो है संख्या बढ़ना

न्याय में देरी

अतः देश में लोकतंत्र को
मजबूत करने व सामाजिक-आर्थिक
न्याय के लिए NHRC को
मजबूत रिए जाने के लिए निम्न
बिंदु 36ए जाने चाहिए -

- परिचित संसाधन 3 पल्लव
कराए जाए
- मानव व अन्य संसाधन जैसे
वित्त पोषण, आदि के लिए
परकार से निर्भरता कम की जाए।
- भूमि निर्माण
- अंतर्राष्ट्रीय विनियमन कार्यक्रम
- फास्ट ट्रायल कोर्ट व डिजिटलीकरण
को बढ़ावा।

देश में कमजोर वर्गों की
आवाज को राष्ट्रीय महत्ता प्रदान करने
के लिए NHRC को मजबूत रिया जाना आवश्यक

12. Discuss how the integration of information and communications technology (ICT) in the dispute resolution processes will help in overcoming the challenges associated with the functioning of courts and Alternative Dispute Resolution (ADR) forums. (250 words) 15

विवेचना कीजिए कि विवाद समाधान प्रक्रियाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का एकीकरण अदालतों एवं वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) मंचों के कामकाज से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने में किस प्रकार सहायता करेगा।

बेहतर न्याय प्रणाली की
संरचना पर बेहतर लोकमंत्र
की नींव रखी जा सकती है।

अदालत व वैकल्पिक विवाद समाधान
मंच (ADR) में कामकाज से जुड़ी
चुनौतियाँ

• लंबित मामलों की संख्या
बढ़ना।

↓
न्याय समय पर नहीं मिला
पाता जो एक अर्थ में
स्वयं ही अन्याय है।

• कसों को प्राथमिकता देना, बच्चों
का निर्णय करना आदि में
यादृच्छिकता पाई जाना।

- धोमो प्रक्रिया
- सुगमता का अभाव विशेषकर दिव्यांग जैसे कमजोर व संवेदनशील वर्ग के लिए।
- खर्चीली प्रक्रिया, कमजोर वर्गों को सोमित करती है।

ICT के माध्यम से विवाद समाधान प्रक्रियाओं में संभावित सुधार

- दूरदराज व कमजोर वर्गों की सुगमता में वृद्धि व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागीदारी कर सकते हैं।
- इससे समय व खर्च में भी कमी होगी।
- न्यायिक प्रक्रिया शीघ्र हो जायेगी।
- अधिक लम्बे समय से लेबित

बेसो को समय के अनुपात में
प्राथमिकता दी जा सकेगी।

→ AI के प्रयोग से मानवीय सीमाओं
को कम किया जा ^{सुनिश्चित} है - जहाँ
काद में बिना जजों द्वारा बिना
निर्णय दिए जाना।

→ लोगों की लीगल जागरूकता में
वृद्धि होगी - कई HC जैसे गुजरात
व सुप्रीम कोर्ट द्वारा लारव रिपोर्टिंग
को अनुमति देना।

बिना इसके साथ ही
बिना पुनर्निर्माणों को भी दूर
रिया जाना चाहिए -

→ डेटा का संरक्षण
→ निजता की सुरक्षा
- डिजिटल डिवाइस कम करना
→ इंटरनेट की पहुँच को सरकार
के सेंजो तक सुगम करना।

→ डिजिटल साक्षरता उपलब्ध करना।
इसके माध्यम से अधिक
क्षेत्र में शान्तिकारी बदलाव आ
सकते हैं।

13. Despite various provisions concerning disqualification of legislators under The Representation of The People Act, 1951, the issue of criminalization of politics is still unresolved to a large extent in India. Discuss.

(250 words) 15

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत विधायकों की निरर्हता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बावजूद, भारत में राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा अभी भी काफी हद तक अनसुलझा है। विवेचना कीजिए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत विधायकों की निरर्हता से संबंधित कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं-

1. 2 साल से अधिक सजा पाने वाले विधायकों की निरर्हता घोषित करना।

2. चुनाव में 20 वर्षों का विवरण देने में विफल होने पर।

3. सामाजिक कृतियों जैसे दूआइत आदि में संलग्न पाए जाने पर आदि।

इन प्रावधानों के बावजूद एसोसिएशन ऑफ़ जस्टिस रिपोर्ट (AJR) के अनुसार अपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या जो 2014 में 34% थी वह 2019 में बढ़कर 43% हो गई है।

अभी भी राजनीति के
अपराधों के कारण

→ अत्यधिक शक्ति पदशक्ति व
वित्तपोषण के कारण

चुनाव में जीत की संभावना
अधिक होती है।

→ राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव

↳ इसके कारण RPA
1951 के प्रावधानों को पूर्ण
अध्यात्म नहीं दिया जाता
व अपराधिक पृष्ठ वाले
लोगों को टिकट दे दी जाती है।

→ चुनाव आयोग (EC) व न्यायपालिका
की असमता

↳ EC को पार्टियों को
अनरजिस्टर्ड करने की शक्ति
नहीं है।

↳ न्यायपालिका में केस
लोकित केसों के अधिक
संख्या के कारण लोकित प्रेरित है।

आंतरिक लोकतंत्र का अभाव

↳ इसके कारण दमशील
डेम्नोक्रासो मुख्य राजनीति में
महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते।

आवश्यक उठाए जाने योग्य कदम

→ चुनाव आयोग को पार्टियों को
अनरजिस्टर करने की शक्ति
प्रदान की जाए।

→ फास्ट ट्रैक कोर्ट

→ जनता को जागरूक बनाया
जाना।

→ चुनाव में काले धन का प्रयोग
रोकना व वर्तमान की परिभाषाओं
में सुधार करना व चुनाव बॉर्ड

→ आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना

→ कठोर कानूनी प्रावधान दिए जाना

→ चुनावों के लो को RTI के तहत
लाना।

संसद-लोकतंत्र की आत्मा
होती है अतः इसकी पहिचान को
बनाए रखना - देश के अस्तित्व के लिए
महत्वपूर्ण है।

14. It is time for reforms, which recognise that urban local bodies (ULBs) need permanent, buoyant revenue sources to match the growing demands of an increasing urban population. Discuss. (250 words) 15

यह सुधारों का समय है जो यह पहचान करता है कि शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को बढ़ती शहरी आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए स्थायी, वृद्धिशील राजस्व स्रोतों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

ULBs (शहरी स्थानीय निकायों) को बढ़ती शहरी आबादी के तहत इन मांगों को पूरा किए जाने की आवश्यकता है -

- मलिन वस्तुओं का पुनर्वासन
- जल, बिजली जैसे सुविधाओं की सतत, निरंतर व वृद्धिशील पहुंच प्रदान करना।
- अवसंरचनात्मक विकास (सड़कें, कोल्ड स्टोरेज आदि)
- शैक्षणिक सुविधाएं
- शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएँ

अतः ULBs को वृद्धिशील राजस्व स्रोतों की आवश्यकता है।

वर्तमान में वित्तीय संरचना में कमी

→ अधिकांश केस व राज्य सरकारों के अनुदानों पर निर्भर।

समग्रतः
→ 2009 से अर्जित वित्तीय संलाभन 10% तक नहीं पहुँचे हैं जबकि ब्राजील, जर्मनी जैसे देशों में यह 40% से अधिक है।

→ कर प्रक्रीकरण की प्रक्रिया में कुशलता की कमी।

→ जो जाने वाली सेवाओं की व्यावहारिक मूल्य, प्रकृतित मूल्य से काफी अधिक होना चाहिए।

→ राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करने में राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव।

अतः निम्न वृद्धिशील राजस्व स्रोतों पर भी बल देना चाहिए -

→ अन्य प्रकार की संपत्ति जैसे खाली पड़े क्षेत्र (vacant land), इमारतों का विरास पर दिए जाना आदि विकल्पों को बढ़ावा देना।

- बंधपत्र जारी करना (Bonds)
- इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- निजी कंपनियों के सरकारी भूमि, क्षेत्र में निवेशों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न किया जा सकता है।
- दी जाने वाली सेवाओं पर यूनिफॉर्म शुल्क आरोपित करना।
- संपत्ति कर के प्रकरण में कुशलता लाना।
- अधिकारियों व अन्य मानव संसाधन को क्षमता निर्माण करना।
- राज्य व केंद्र सरकार के साथ ULBs के मध्य सहयोगी संबंधों को बढ़ावा देना।
- राज्य विज्ञ आयोग की शक्तियों को बढ़ावा देना।
- अनु 280 के तहत DFEC को शामिल कर ULBs के राजकोषीय व्ययों को समग्र राजकोषीय व्यय में जोड़े जाना।
- इस माध्यम से ही वास्तविक अर्थों में लोगों का शासन स्थापित होगा।

15. The role of the civil society organisations (CSOs) in India is changing in contemporary times and has become increasingly more complex. Discuss.

(250 words) 15

समकालीन समय में भारत में नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की भूमिका बदल रही है और निरंतर अधिक जटिल होती जा रही है। चर्चा कीजिए।

नागरिक समाज, समाज का प्रतिबिम्ब होते हैं और समाज की कमियों को भी दूर करके सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से कल्याणकारी लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पहले के समय में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका

- कमजोर वर्गों को समर्थन देना
- कमजोर वर्गों के हितों को प्रतिनिधित्व देना तथा इनके हितों को सरकार तक पहुँचाना
- जनता का सामना निमीषा दिया जाना सु-शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी उपलब्ध करना
- जन जागरूकता के कार्यक्रमों का संचालन करना इसके लिए

पारंपरिक तरीके जैसे - वार्ता करना, नुक्कड़ नाटक करना, आदि शामिल था।

→ सरकार व नागरिक समाज के मध्य सहयोगात्मक भावना की उपस्थिति थी।

वर्तमान में भारत में नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की जटिल होती स्थितियाँ

→ सोशल मीडिया साइट्स इंटरनेट की उपस्थिति आदि के कारण इनके क्षेत्रों, क्षेत्राधिकार, कर्तव्यों को व्यापकता मिली है जिससे संरचना जटिल हुई है।

→ लोगों में बढ़ती शिक्षा व जागरूकता के कारण CSOs की महत्ता बढ़ी है जिससे इनके

वित्तीय संसाधनों में भी
जखिरता बढी है ए- विदेशी से
प्राप्त अनुदान आदि।

- पारवर्षिता बढने के कारण इनकी
जमावदेदितता में वृद्धि हुई है।
- ऑडिटिंग व जनता द्वारा स्वयं
मूल्यांकन किया जाना।
- सरकार के साथ विश्वास-घाटे
की स्थिति।
- अंतराष्ट्रीय विनियमन बढा है।

वर्तमान के
अंशमणशील समाज व विश्व में
200 की प्रकृति में परिवर्तन आना
की स्वाभाविक है। आवश्यकता है
कि इनके जनकल्याण के महत्वपूर्ण
निर्वात के बिंदुओं को भरने का
महत्वपूर्ण माध्यम बनाया जाए।
इससे लोकतंत्र में
जातिशीलता व लोचशीलता
(flexibility) का विकास होगा।

16. Though the Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) aims to address the inequity in development in India, there are a number of issues which plague the scheme. Discuss. (250 words) 15

वैश्वीकरण के युग में, विकेंद्रीकरण आधारभूत प्रतिकारी प्रवृत्ति है, जो भारत में विकास प्रक्रिया का समावेशी होना सुनिश्चित कर सकती है। चर्चा कीजिए।

MPLADS योजना के तहत सांसदों को अपने निर्वाचित क्षेत्रों में विकास योजना के लिए 5 करोड़ रु की धनराशि दी जाती है। इससे- असमानताओं में कमी आती है।

MPLAD द्वारा असमानताओं को कम किया जाना

→ यह विकास योजनाओं में SC/ST, OBC वर्ग को प्रथमिकता प्रदान करता है। ऐसे क्षेत्रों में विकास योजनाओं में निम्न वर्ग का भी जीवन स्तर में सुधार होता है।

→ जिले के स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इससे क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित होता है।

→ यह शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्र, विजली जैसे मूलभूत आवश्यकताओं (बेसिक) अवसंरचना पर बल देता है

→ इससे लोगों से अपेक्षित लोगों की आकांक्षा पूर्ण होती है जिससे लोगों का सरकार में विश्वास बढ़ता है विशेषकर कमजोर वर्ग में साम्प्रदायिक मान का भाव बढ़ता है।

वर्तमान में MALAYSIA में कमियाँ

→ कुछ का सही ढंग से भू-टिलीग्राफेशन में लिया जाता

→ स्थानीय लोगों की भागीदारी का अभाव होता है।

→ वोट बैंक की दृष्टि से लगातार व्यय करने के कारण आखिरी वर्षों में व्यय करने पर बल दिया जाता है।

→ टॉप टू बॉटम अप्रोच

- शक्ति के प्रयोजन के
सिद्धान्त के विरुद्ध।
- 5 करोड़ की धनराशि अपयस्त्रि

सुधार के उपाय -

- फंड को व्यपगत (Lapsable)
बनाया जाना।
- प्रमुख धनराशि से निर्मित
संरचनाओं की पर्याप्त निगरानी
व मॉनिटरिंग की जाना।
- संसाधनों को अनुकूलतम दोहन
सुनिश्चित हो।
- विकास योजना के निमग्न में
स्थानीय लोगों की भागीदारी
को बढ़ाना।
- बॉटम द अप अप्रोच
- विशेषज्ञता मलाह को
सुनिश्चित करना।
इन प्रयासों के माध्यम
से MPLADS असमानताओं को
कम करने में सक्षम हो सकेगी।

17. Highlighting the factors responsible for the growth of EdTech sector in India in recent times, discuss its benefits. Also, state the concerns associated with it. (250 words) 15

हाल के दिनों में भारत में एडटेक क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालते हुए, इसके लाभों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इससे जुड़ी चिंताओं का भी उल्लेख कीजिए।

एडटेक का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का उपयोग।
विश्व जहाँ वर्तमान में एडटेक लगातार सूर्योदय उद्योग (sunrise industry) के रूप में बढ़ रहा है।

एडटेक क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी कारक

→ वर्तमान विश्व की मांग के अनुरूप

↳ शिक्षा को उच्च स्तरीय बनाने में

↳ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा सृजित करने के लिए

→ कोरोना महामारी

↳ लॉकडाउट में एडटेक की

क्रिया को और तेज कर दिया।

↳ एडटेक का उपयोग निम्न वर्गों तक भी पहुँचा है।

तकनीक की उपयोगिता

- ↳ शिक्षा सस्ती हो जाती है
- ↳ स्थान व समय की
विशिष्टता समाप्त हो
जाती है।
- ↳ दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँच

रोजगार

- ↳ बड़े स्तर पर रोजगार का
सृजन (यू-एडिआ भाषाशिक्षण
YouTube चैनल आदि का बनाव)
- ↳ भारत में IT क्षेत्र का
बढ़ावा व सेवा क्षेत्र
में वृद्धि
- ↳ एस्टेनमेंट शोज का बढ़ना

सरकारी काम

- ↳ सरकार द्वारा शिक्षा में
डिजिटलीकरण को बढ़ावा
- ↳ SWAYAM पोर्टल
- ↳ MOOC (मॉसिल ऑनलाइन
आपन कोर्सेस)
- ↳ नई शिक्षा नीति आदि।

उड़ते के नांग

- शिक्षा में स्थान व समय की आवश्यकता होने से कमजोर वर्ग, दूरदराज क्षेत्रों को समावेशित करना बर्बाद
- नवाचार को बढ़ावा
- अंतरक्रिय विनियमन को बढ़ावा
- शिक्षा को रचनात्मक बनाया जा सकता है।
- रोजगार के अवसर
- कम खर्चीला

चिंतारं

- डिजिटल डिविड
- ग्रामीण विज्ञापन
- इंटरनेट की पहुँच न होना
(ए-ग्रासनेट परियोजना)
- डिजिटल साक्षरता का अभाव
(एन डिजिटल साक्षरता अभियान)
- निजता की सुरक्षा
- डेटा का संरक्षण।
इन चिंतारं को दूर करने
- उड़ते के माध्यम से भारत की युवा जनसंख्या को अविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है।

18. Bring out the role of Accredited Social Health Activist (ASHA) workers in delivering health services in rural India. Also, suggest the measures that can be taken to overcome the challenges faced by them. (250 words) 15

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को दूर करने के उपाय भी सुझाइए।

आशा स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं
जिनका गठन राष्ट्रीय ग्रामीण
स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण
भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की
पहुँच को बढ़ावा देने के लिए
किया गया था।

आशा की भूमिका

- घर-घर जाकर लोगों को
स्वास्थ्य सुविधाओं व
योजनाओं के संबंध में जानकारी
देना।
- आवश्यक सरकारी दवाओं
व सुविधाओं का वितरण
करना व- महिलाओं को आयरन
व कैल्शियम की दवा वितरित
करना।

→ गर्भवती व दूध-पिलाने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ-साथ पौष्टिक भोजन तक पहुंच उपलब्ध कराना।

→ संचागत डिलीवरी को बढ़ावा देना।

→ जनजागरूकता का कार्य करना जैसा - कोरोना महामारी के दौरान किया गया वह इनिशिएटिव हमने भी इसे - पुरस्कृत किया है।

आशा है, सामुदायिक जल व पानी चुन लिया।

→ आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कमी।

→ निम्न कार्य - की परिस्थितियाँ व सामाजिक सुरक्षा आदि का अभाव

→ मानवीय संसाधनों की कमी → काम को बॉर्डर बट जाता है → मानसिक अवसाद

→ सुविधाओं का अभाव व -
कई - कई किलोमीटर तक पैदल
भ्रमना पड़ता है।

धुनीतियों को दूर करने के उपाय

- वित्तीय संसाधनों, निश्चित
आय, सामाजिक सुरक्षा व
सुविधाओं से सुनिश्चित किया
जाए।
- क्षमता निर्माण → बेहतर परिणाम
- तकनीक उपलब्ध कराई जाए →
- कार्य में बुद्धिमत्ता व दक्षता आणकी
- पदोन्नति पर बल
- प्रोत्साहन को बढ़ावा देना।
स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त
सुधार व स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी
असंतुलन व असमानता को अशांति
के माध्यम से क्रान्तिकारी रूप से समाप्त
किया जा सकता है अतः उन्हें पर्याप्त
व बेहतर क्षमता निर्माण व अवसर
प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

19. Discuss the various concerns that have arisen for India after the Taliban takeover of Afghanistan. Also, suggest the measures that India should take in the given context. (250 words) 15

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर अधिकार करने के बाद भारत के लिए उत्पन्न विभिन्न चिंताओं की विवेचना कीजिए। साथ ही, उन उपायों का सुझाव दीजिए जो इस संदर्भ में भारत द्वारा अपनाए जाने चाहिए।

सितम्बर 2021 में तालिबान औपचारिक रूप से अफगानिस्तान पर अधिकार कर लेता है। यह प्रक्रिया अमेरिका के अफगानिस्तान (Afg) के छोड़ने के बाद आरंभ हुई थी।

तालिबान के अधिकार से भारत के लिए उत्पन्न चिंतारें

→ आतंकवाद को पुनः बढ़ावा मिलना

इससे भारत की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

→ भारत द्वारा विपक्षी निवेश की सुरक्षा संबंधी संशय उत्पन्न होना।

→ चीन व पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका

↳ भारत के रणनीतिक हितों के विपरीत हैं।

→ क्षेत्रीय अस्थिरता

↳ ASG के अस्थिर होने से सम्पूर्ण दक्षिण में अस्थिरता आएगी जिससे सभी देशों की सम्प्रभुता व शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

उपाय जो भारत द्वारा अपनाए जाने चाहिए

→ अंतराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से तालिबान को अलग-थलग किया जाना।

→ इसी के माध्यम से पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को अंतराष्ट्रीय मंचों पर रोकना

- अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के माध्यम से लोगों के अधिकारों व भारतीय निवेश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- आवश्यक पदार्थों की उपलब्धता करना जैसे - गेहूँ, चावल, चीनी, दवाएँ आदि।
- देश की आंतरिक सुरक्षा के तंत्र को मजबूत करना।
- कम्यूनिस्ट आतंकवाद निरोध पर अंतराष्ट्रीय सहयोग प्रिमित करना।
- आतंकवाद से संबंधित चुनौती से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक व गुप्त संरचनाओं को मजबूती प्रदान करना।
- अफगानिस्तान में स्थिरता के माध्यम से ही द. एशिया व विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है।

20. Bangladesh is not only a key part of India's "Neighbourhood First policy" but also crucial for the "Act East policy". In this context, discuss the steps taken by the two countries to strengthen their relationship.

(250 words) 15

बांग्लादेश न केवल भारत की "नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी" का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, दोनों देशों द्वारा अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए।

भारत - बांग्लादेश के साथ लगभग 5096 km का बॉर्डर साझा करता है। इससे ज्ञात होता है कि भारत के पड़ोसी देश होने के साथ-साथ भारत की भौतिक सुरक्षा व इष्ट परिस्थिति से संबंधों की दृष्टि से बांग्लादेश महत्वपूर्ण देश है।

भारत - बांग्लादेश के ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक कारकों के कारण बेहतर संबंध रहे हैं।

नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा

→ बेहतर पड़ोसी देश के साथ संबंधों से देश की बेहतर भौतिक

सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है

- ↳ अवैध-हथियारों का आगमन
- ↳ नशीले पदार्थ
- ↳ नकली नोट
- ↳ प्रतिबंधित दवाएँ
- ↳ अवैध-उपकरण

↓
देशों को सुरक्षा को खतरा
पहुँचाते हैं।

→ बेहतर आर्थिक विकास

- ↳ व्यापार सुगमता पूर्वक
- ↳ परिवहन में लागत कम
- ↳ लोगों के मध्य कनेक्टिविटी
बढ़ती है।

एवट ईस्ट पॉलिसी में बांग्लादेश
की भूमिका

- एवट ईस्ट पॉलिसी के लिए
द्वार का कार्य अर्थात् दोनों क्षेत्रों
को जोड़ने का कार्य करता है।
- बांग्लादेश के माध्यम से ईस्ट
देशों तक कनेक्टिविटी संभव हो
सकती है।
- व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है।

दोनों देशों द्वारा 36th G8 के

- 2014 में समुद्री सीमा विवाद को सुलझाना।
- 2015 में मुक्ति विवाद को शांतिपूर्वक ढंग से निपटाया जाना।
- व्यापार को बढ़ावा देने पर बल।
- भारत द्वारा बांग्लादेश में क्षमता-निर्माण पर बल दे-प्रशिक्षण देना।
- BBIN मोटर व्हेकल एग्रीमेंट में दोनों देश शामिल हैं।
- BIMSTEC के माध्यम से सहयोग बढ़ावा।
- IORA (हिंद महासागर रिम एसोसिएशन) के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में सहयोग।
- आपदा संबंधित सहयोग व चुनौती प्रणाली का विकास करना इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बांग्लादेश महत्वपूर्ण स्थान रखता है।